भारत की पाक नीति : दिशाहीनता की बजाए कूटनीतिक समर्पण की जरूरत

''मशहूर लेखक लैविस कैरोल की विश्वविख्यात बच्चों की कहानी 'ऐलिस इन वंडरलैंड' में मशहूर वाक्य है, ''यदि आपको नहीं मालूम कि आप कहां जा रहे हैं तो आप किसी भी मार्ग से जा सकते हैं।'' हालांकि इस उपन्यासकार ने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान नीति को लेकर नहीं लिखी थी, पर यह मोदी जी की पाकिस्तान बारे 'कभी हां- कभी न' की संयोगिक नीति का जीता-जागता सबूत है। मशहूर स्तंभकार आकार पटेल ने मोदी सरकार द्वारा 19 महीने के कार्यकाल में पाक नीति पर 9 बार अलटा-पलटी को चिन्हित किया है। यह भी तब जब चुनाव से पहले श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान के प्रति कठोर नीति की धुरंधर वकालत कर तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की कड़ी सार्वजनिक आलोचना की गई क्योंकि डा. मनमोहन सिंह बातचीत द्वारा भारत-पाक के रिश्तों में खटास कम करने की कोशिश कर रहे थे।

सरकार तो कभी-कभी यह दिखाने की कोशिश भी करती है कि कांग्रेस पार्टी ही पाकिस्तान के साथ शांति संबंधों का विरोध कर रही है। यह बिल्कुल बेबुनियाद है। अपनी सरकार के दौरान कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के साथ काफी बुद्धिमानी एवं संवेदनशीलता के साथ संबंध निभाए हैं फिर चाहे 1965 की लड़ाई के दौरान मिलिट्री कार्रवाई हो या 1971 में बंगलादेश की स्वतंत्रता या 1984 में सियाचिन ग्लेशियर की वापसी। इसके अलावा 1966 में ताशकंद या 1972 में शिमला समझौते या राजीव गांधी द्वारा किए गए न्यूक्लियर सी.बी.एम. समझौते में भी भारत ने बड़ी ही जिम्मेदारी से अपने कूटनीतिक संबंध निभाए।

पाकिस्तान के साथ संबंधों को निभाते वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने हमेशा राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा। तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने हमेशा पाकिस्तान के साथ संबंधों के मामले में संसद को विश्वास में लिया एवं विपक्षी दलों और मीडिया को इसकी पूरी जानकारी दी। अब हमारे देश में ऐसी सरकार है जिसके सबसे वरिष्ठ मंत्रियों तक को यह पता नहीं होता है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान की यात्रा करने वाले हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। भारत-पाकिस्तान संबंध पूरे देश से ताल्लुक रखते हैं और इन्हें किसी की भी व्यक्तिगत सम्पत्ति या प्रभुत्व नहीं माना जा सकता।

श्री मोदी की पाकिस्तान नीति क्या है? एक बार उन्होंने कहा था कि 'बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते', तो कभी वह कहते हैं कि '26/11 को जिन आतंकवादियों ने मुंबई में आतंक फैलाया पहले उनको सजा दी जाए' और फिर वह कहते हैं कि 'एन.एस.ए.

रणदीप सिंह सुर्जेवाला

स्तर की वार्ता तभी होगी जब उसकी चर्चा का विषय आतंकवाद होगा'। कभी वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को साड़ी एवं शॉल भेंट करते हैं और अब नवाज शरीफ जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए यकायक पाकिस्तान जाते हैं। इन दोनों ही बातों के बीच बेपेंदी के लोटे की तरह डगमगाती हुई सरकार को देश हित को सर्वोपरि रखने वाली कोई भी पार्टी समर्थन नहीं देगी, खासकर तब जब पाकिस्तान की ओर से कोई भी सकारात्मक रवैया दिखाई न दे।

आज की स्थिति में कोई भी यह नहीं जानता है कि पिछले कुछ महीनों में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण मोदी सरकार ने अपनी पाकिस्तान नीति में यू-टर्न ले लिया। भारत के नागरिकों को अभी भी यह नहीं पता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने बैंकॉक में अपनी मीटिंग में क्या चर्चा की एवं पाकिस्तान के साथ विस्तृत चर्चा कैसे शुरू होगी। क्या प्रधानमंत्री यह किसी बाहरी शक्ति के दबाव में कर रहे हैं या फिर यह व्यक्तिगत वाहवाही बटोरने के लिए किया जा रहा है? क्या भारत को इस सबकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के सामने भारत के हितों की बलि दी जा सकती है? पूरा देश इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है।

हाल ही में की गई लाहौर यात्रा देश की समस्याओं से मीडिया का ध्यान हटाने का एक कुत्सित प्रयास है। तेल की कीमतें इतिहास में सबसे निचले स्तर पर होने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था पिछले 19 महीनों में ठप्प क्यों हो गई? देश में नए रोजगार न पैदा होने की समस्या से लेकर ढांचागत विकास (सड़क, बिजली इत्यादि) में भारी मंदी मोदी जी के नेतृत्व में ही आई है। उद्योग और व्यवसाय लगभग ठप्प होने की कगार पर हैं। इन्हीं कारणों से भाजपा बिहार में औंधे मुंह गिरी और प्रधानमंत्री का ताबड़तोड़ चुनाव अभियान भी व्यर्थ साबित हुआ। इसके ठीक बाद गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव एवं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण उपचुनाव में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। आज भी मोदी जी के दो वरिष्ठ मंत्रियों श्रीमती सुषमा स्वराज एवं श्री अरुण जेतली पर पद के दुरुपयोग तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के भाजपाई मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं। क्या यह पूरी कवायद देश का ध्यान बांटने का तरीका है?

प्रधानमंत्री जी को कैमरा एवं सैल्फी का बहुत शौक है और वह सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। लेकिन भारत की पाकिस्तान नीति ठोस परिणामों के अलावा किसी और चीज से नहीं चल सकती। पाकिस्तान ने 26/11 के मुम्बई हमले के आतंकियों को आज तक सजा नहीं दी। इसके बिल्कुल विपरीत आतंकवाद के मास्टरमाईंड लखवी को भी छोड़ दिया गया और हमारी सरकार ने उसका विरोध तक नहीं किया। सीमापार से घुसपैठ भी कम नहीं हुई। असलियत तो यह है कि इस साल घुसपैठ में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 19 महीने में 900 बार नियंत्रण रेखा का उल्लंघन हुआ। मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान को साड़ियां एवं शॉल भेंट किए जाने के बाद भी पाकिस्तान ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन (एम.एफ.एन.) का दर्जा आज तक भी नहीं दिया है।

बातचीत पर गोपनीयता बनाकर या फोटो खिंचवाने से पाकिस्तान नीति पर मोदी सरकार की दिशाहीनता छिपेगी नहीं। पाकिस्तान के साथ कोई भी चर्चा ठोस एवं भारत के हित में होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में हर भारतीय स्टेकहोल्डर है और पाकिस्तान नीति में हर देशवासी को विश्वास में लेना जरूरी है। कश्मीर या आतंकवाद पर किसी भी तरह का समझौता देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी।

(लेखक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मीडिया प्रभारी हैं।)